



साप्ताहिक सूचना पत्र



दिनांक 19.09.2026 से 25.09.2026

9 वाँ संस्करण

श्री मनोहर लाल

माननीय केंद्रीय विद्युत तथा आवासन
एवं शहरी कार्य मंत्री





विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

सप्ताह की प्रमुख उपलब्धियाँ

- 1 | भारत ने बिना किसी कमी के 248.11 GW की अधिकतम विद्युत मांग पूरी की
- 2 | केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत के निवारक और भविष्य-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर दिया
- 3 | विद्युत राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नाईक ने ऊर्जा सहयोग पर यूरोपीय संघ के ITRE प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक की
- 4 | विद्युत मंत्रालय, POWERGRID और MeitY ने SiC-आधारित VSC-HVDC प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए मिलकर काम किया
- 5 | NTPC ने लगातार तीसरे वर्ष EPRI प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पुरस्कार 2025 प्राप्त किया
- 6 | EESL ने कार्बन प्रबंधन और पैसिव कूलिंग समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक समझौता जापनों पर हस्ताक्षर किए
- 7 | RECPDCL ने पूरे भारत में 76 संस्थानों में रूफटॉप सोलराइजेशन के लिए ICAR के साथ MoA पर हस्ताक्षर किए

साप्ताहिक सूचना पत्र

19.09.2026 से 25.09.2026



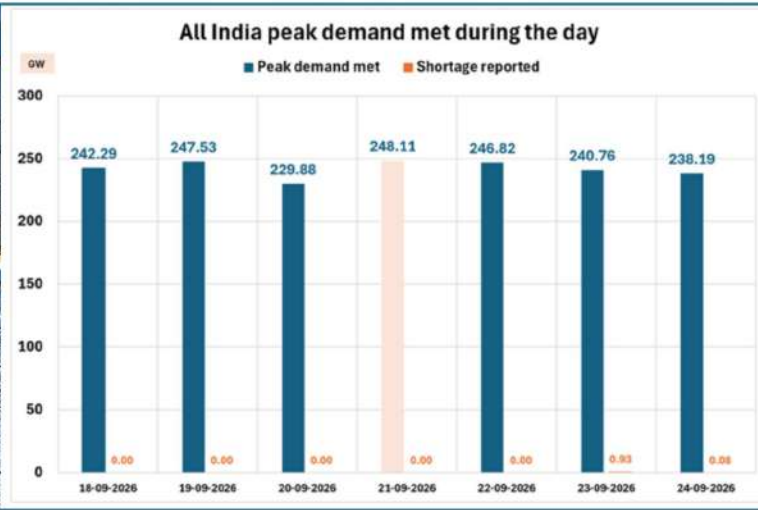
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

सत्यमेव जयते

24 सितंबर, 2026

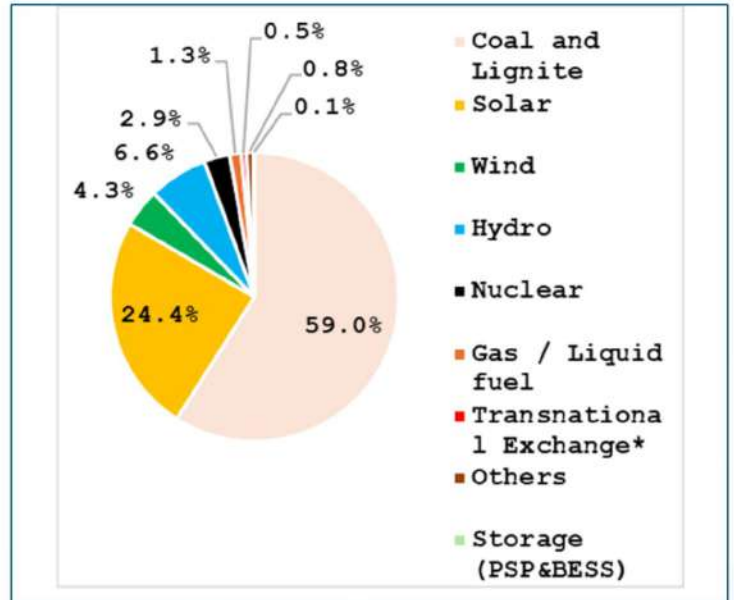
भारत ने बिना किसी कमी के 248.11 GW की अधिकतम विद्युत मांग पूरी की

नीचे दिए गए चार्ट में 18 सितंबर से 24 सितंबर 2026 तक दर्ज की गई दैनिक अधिकतम विद्युत मांग की पूर्ति और विद्युत कमी को दर्शाया गया है।



साप्ताहिक अधिकतम मांग के समय कुल विद्युत उत्पादन

Generation source	Generation (GW)	Share of Total generation (%)
Gas / Liquid fuel	3.3	1.3%
Hydro	16.7	6.6%
Nuclear	7.3	2.9%
Coal and Lignite	149.1	59.0%
Wind	11.0	4.3%
Solar	61.6	24.4%
Storage (PSP&BESS)	0.2	0.1%
Others	2.1	0.8%
Transnational Exchange*	1.4	0.5%
TOTAL	252.7	100.0%



इसी अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर अधिकतम विद्युत मांग की पूर्ति और ऊर्जा खपत में क्रमशः 8.3% और 7.7% की वृद्धि दर्ज की गई।

साप्ताहिक सूचना पत्र

19.09.2026 से 25.09.2026



विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

20 सितंबर, 2026

केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत के निवारक और भविष्य-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर दिया



केंद्रीय विद्युत एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक निवारक और भविष्य-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया, जिसमें भारत के ऊर्जा संक्रमण और तेजी से बढ़ते शहरों में स्थिरता को समाहित किया जा रहा है। उन्होंने यह बात नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा आयोजित "पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य" विषयक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु भी गरिमायुक्त उपस्थिति में उपस्थित थीं। विद्युत और शहरी कार्य, दोनों क्षेत्रों की अपनी जिम्मेदारियों का उल्लेख करते हुए माननीय मंत्री ने रेखांकित किया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दैनिक जीवन में तेजी से दिखाई दे रहे हैं।

भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। अब गैर-जीवाश्म स्रोत स्थापित क्षमता का लगभग 55% है और इनकी क्षमता 304 GW से अधिक है। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और मेट्रो नेटवर्क जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के विस्तार के माध्यम से स्वच्छ शहरी परिवहन को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे भारत का शहरीकरण अधिक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल बन रहा है। मंत्री ने रेखांकित किया कि जलवायु परिवर्तन केवल चिंता का विषय नहीं, बल्कि गंभीर चिंतन, सामूहिक जिम्मेदारी और समयबद्ध कार्रवाई का विषय है। उन्होंने कहा कि जब हम केवल चिंता करने से आगे बढ़कर इस विषय पर गहराई से विचार करना शुरू करते हैं, तो समस्या का समाधान सामने आने की संभावना बनती है। उन्होंने आगे जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन अब केवल वैज्ञानिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह मानव सभ्यता के अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, मूल्यों और जीवनशैली के दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह व्यापक समझ समाधान सामने लाने में सहायक हो सकती है।



साप्ताहिक सूचना पत्र

19.09.2026 से 25.09.2026



विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

24 सितंबर, 2026

विद्युत राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नाईक ने ऊर्जा सहयोग पर यूरोपीय संघ के ITRE प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक की

विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नाईक ने नई दिल्ली में यूरोपीय संसद की उद्योग, अनुसंधान और ऊर्जा समिति (ITRE) के प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, कार्बन बाजार, ग्रीन हाइड्रोजन, जैव ऊर्जा, विद्युत अनुबंध, कूलिंग समाधान, परमाणु ऊर्जा, लचीलापन और ऊर्जा भंडारण तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने जारी पहलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और सहयोग को और गहरा करने के अवसर तलाशे।

माननीय राज्य मंत्री ने भारत के तेजी से बदलते विद्युत क्षेत्र तथा एक सुदृढ़, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा प्रणाली के निर्माण के लिए देश के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के विस्तार में भारत की प्रगति के बारे में जानकारी दी, जिसमें निर्धारित लक्ष्य से काफी पहले NDC प्रतिबद्धताओं को हासिल करना, पारेषण और वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करना, ऊर्जा भंडारण और स्मार्ट-ग्रिड समाधानों को लागू करना तथा परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और ग्रीन हाइड्रोजन को आगे बढ़ाना शामिल है।



साप्ताहिक सूचना पत्र

19.09.2026 से 25.09.2026



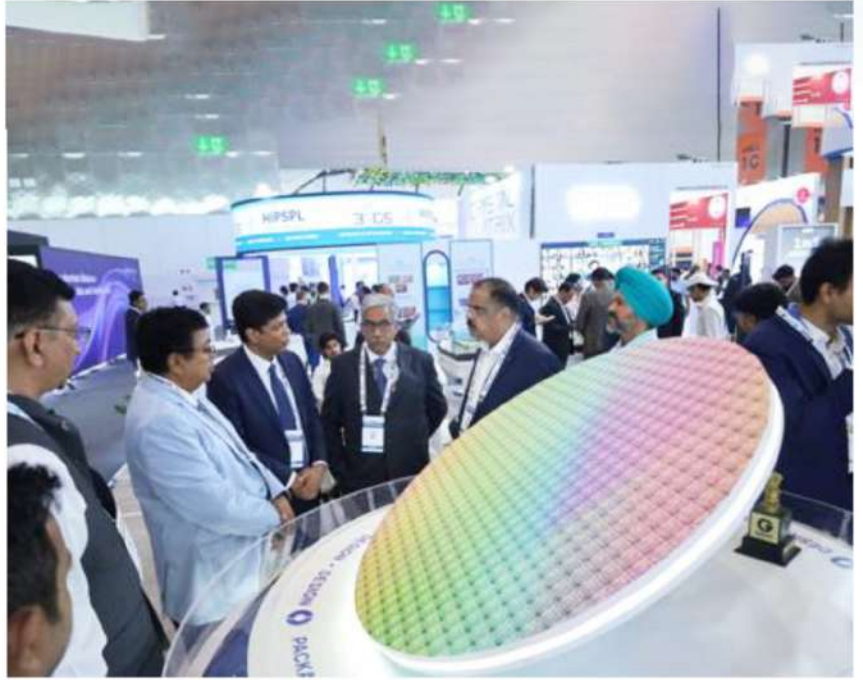
विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

19 सितंबर, 2026

विद्युत मंत्रालय, POWERGRID और MeitY ने SiC-आधारित VSC-HVDC प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए मिलकर काम किया

विद्युत मंत्रालय, POWERGRID और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने VSC-HVDC पावर सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) MOSFET-आधारित पावर सेमीकंडक्टर मॉड्यूल के स्वदेशी डिजाइन और विकास को समर्थन देने के लिए हाथ मिलाया है। इस सहयोग की घोषणा 17-19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित SEMI-CON India 2026 के दौरान की गई।

यह घोषणा माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद, विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. डी. साईबाबा, POWERGRID के निदेशक (संचालन) श्री नवीन श्रीवास्तव और POWERGRID के OSD (परियोजनाएं) श्री अखिलेश पाठक सहित अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में की गई।



इस पहल का उद्देश्य उन्नत HVDC प्रौद्योगिकी में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करना है। स्वदेश में विकसित मॉड्यूल का प्रदर्शन बिहार में POWERGRID की 1,000 MW पुसौली VSC-HVDC परियोजना में प्रस्तावित है।



साप्ताहिक सूचना पत्र

19.09.2026 से 25.09.2026



विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

18 सितंबर, 2026

NTPC ने लगातार तीसरे वर्ष EPRI प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पुरस्कार 2025 प्राप्त किया



NTPC को अमेरिका के Electric Power Research Institute (EPRI) से Technology Transfer Award (TTA) 2025 प्राप्त हुआ है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब NTPC को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। यह पुरस्कार 14 से 18 सितंबर 2026 तक अमेरिका के इलास, टेक्सास में आयोजित EPRI Generation Advisory and Council Meetings के दौरान प्रदान किया गया, जिसमें दुनिया भर की प्रमुख विद्युत उपयोगिता कंपनियों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और ऊर्जा क्षेत्र के पेशेवरों ने भाग लिया।

NTPC को यह सम्मान NTPC तेलंगाना में EPRI Self-Directed Fund (SDF) के तहत किए गए एक अनुसंधान परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मिला, जो उन्नत नियंत्रण लूप ट्यूनिंग के माध्यम से प्रक्रिया मापदंडों के अनुकूलन पर केंद्रित थी। इस परियोजना से प्राप्त सीख को COS C&I और CST टीमों द्वारा अपनाया गया और NTPC के विभिन्न स्टेशनों की 45 इकाइयों में लागू किया गया।

इस अवसर पर NTPC के प्रतिनिधि ने EPRI Generation Council और उद्योग जगत के नेताओं के साथ चल रही सहयोगात्मक पहलों, उभरती प्रौद्योगिकियों और विद्युत क्षेत्र के सामने आने वाली भविष्य की चुनौतियों पर रणनीतिक चर्चाओं में भी भाग लिया। यह सम्मान अपनी उत्पादन परिसंपत्तियों में विश्वसनीयता, दक्षता और स्थिरता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने, नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के प्रति NTPC की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

19.09.2026 से 25.09.2026



विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

EESL ने कार्बन प्रबंधन और पैसिव कूलिंग समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए



Energy Efficiency Services Limited (EESL) ने M/s Raygas Engineering India Private Limited और M/s Thermogreen Cool के साथ भारत में ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन आकलन, कार्बन प्रबंधन, स्थिरता, ESG और डीकार्बोनाइजेशन पहलों पर सहयोग करने तथा नवीन पैसिव कूलिंग और ऊर्जा दक्षता समाधानों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इन साझेदारियों का उद्देश्य सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और संस्थागत हितधारकों को कार्बन में कमी और सतत विकास की दिशा में मापनीय उपायों की पहचान और क्रियान्वयन में सहायता करना है। ये साझेदारियां ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के क्रियान्वयन में EESL के अनुभव का लाभ उठाकर ऐसे बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले प्रोजेक्ट विकसित करेंगी, जो भारत के जलवायु और स्थिरता संबंधी उद्देश्यों में योगदान दें।

इन सहयोगों के माध्यम से उन्नत कूल-रूफ प्रौद्योगिकियों की तैनाती को सुगम बनाया जाएगा, जिससे इमारतों में ऊष्मा का प्रवेश कम करने, तापीय आराम में सुधार, कूलिंग की मांग घटाने और जलवायु लचीलापन बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा संस्थानों, किफायती आवास और अन्य गर्मी से प्रभावित क्षेत्रों में इनके उपयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। यह भारत के ऊर्जा दक्षता, सतत अवसंरचना और जलवायु अनुकूलन के लक्ष्यों को समर्थन देगा।

ये समझौता ज्ञापन स्थिरता, कार्बन प्रबंधन और जलवायु कार्रवाई संबंधी समाधानों पर संगठन के बढ़ते फोकस के साथ-साथ बढ़ते तापमान और कूलिंग की बढ़ती मांग से निपटने वाली नवीन स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

19.09.2026 से 25.09.2026



विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF
POWER

23 सितंबर, 2026

RECPDCL ने पूरे भारत में 76 संस्थानों में रूफटॉप सोलराइजेशन के लिए ICAR के साथ MoA पर हस्ताक्षर किए



REC Power Development and Consultancy Limited (RECPDCL), जो विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम REC Limited की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 76 ICAR संस्थानों में ग्रीड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक (PV) प्रणालियों के क्रियान्वयन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए हैं। ICAR, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय के लिए शीर्ष संगठन है।

समझौते के तहत कुल 11,109.87 kW (11.1 MW) क्षमता की रूफटॉप सोलर PV प्रणालियां टर्नकी आधार पर स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 1.73 करोड़ यूनिट स्वच्छ बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करने और भारत के कृषि अनुसंधान अवसंरचना में सतत ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने में योगदान मिलेगा।

परियोजनाओं का वित्तपोषण ICAR द्वारा किया जाएगा, जबकि RECPDCL नामित टर्नकी कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करेगा। RECPDCL अपने पैनल में शामिल EPC-सह-O&M एजेंसियों के माध्यम से डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग सहित संपूर्ण कार्यान्वयन करेगा। इसके बाद पांच वर्षों तक व्यापक संचालन एवं रखरखाव (O&M) किया जाएगा।

यह पहल सरकारी संस्थानों में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा दक्षता तथा सतत विकास के भारत सरकार के व्यापक उद्देश्यों को समर्थन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

19.09.2026 से 25.09.2026



विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

दैनिक जागरण (21 सितंबर, 2026)

वैश्विक ऊर्जा मंच पर मनोहर लाल ने मजबूती से रखी भारत की बात
वैश्विक ऊर्जा मंच पर मनोहर लाल ने मजबूती से रखी भारत की बात



मनोहर लाल खट्टर ने वैश्विक ऊर्जा मंच पर भारत की बात रखी।

नई दिल्ली, 21 सितंबर: भारत के प्रधानमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वैश्विक ऊर्जा मंच पर भारत की बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत एक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

दैनिक नवज्योति (22 सितंबर, 2026)

2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा लक्ष्य पर जोर

एजेंसी/नवज्योति, चेन्नई। भारत का 8वां 'विंडजी इंडिया 2026' सम्मेलन 7 से 9 अक्टूबर 2026 तक चेन्नई ट्रेड सेंटर में आयोजित होगा। देश की कुल स्थापित पवन क्षमता 58.52 गीगावाट तक पहुंच गई है, और उद्योग ने 2030 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। सम्मेलन में विनिर्माण, अपतटीय पवन ऊर्जा और रीपायरिंग पर विशेष फोकस रहेगा। एमएनआरडी के संयुक्त सचिव राजेश कुलहरी, आईडब्ल्यूटीएमए के सीईओ आदित्य प्यासी, उपाध्यक्ष डॉ. सारवन्नन मणिकम, और सचिव दिनेश जगदाले ने देश की ऊर्जा सुरक्षा और स्वदेशी विनिर्माण को मजबूत करने पर बल दिया। इस दौरान घरेलू टबाइन विनिर्माण क्षमता 24 गीगावाट वार्षिक हो गई है और निर्यात 12,000 करोड़ रुपये पार कर गया है।

बिजनेस रेमेडीज़ (24 सितंबर, 2026)

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर की सार्थक चर्चा

नई दिल्ली | एजेंसी: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऊर्जा और जलवायु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर की सार्थक चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच ऊर्जा और जलवायु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर की सार्थक चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच ऊर्जा और जलवायु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर की सार्थक चर्चा हुई।

अमर उजाला (19 सितंबर, 2026)

उत्पादन पकड़ल में 1000 तो फिर में होगा 624 मेगावाट बिजली का उत्पादन
सर्दियों में बिजली खरीद से मिलेगी राहत, बढ़ेगा 1624 मेगावाट उत्पादन

राजेश शर्मा
जम्मू। जम्मू-कश्मीर को सर्दियों में बिजली की खरीद से राहत मिलने वाली है। प्रदेश की दो बड़ी परियोजनाएं दिसंबर में उत्पादन शुरू कर देंगी। इन परियोजनाओं से बिजली की उत्पादन क्षमता में करीब 1624 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही प्रदेश में बिजली उत्पादन 3540 मेगावाट से बढ़कर 5164 मेगावाट हो जाएगा। प्रदेश में दिसंबर तक बिजली उत्पादन लगभग 29 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। जिन दो परियोजनाओं का निर्माण दिसंबर में पूरा होगा है उनमें 1000

दोनों परियोजनाओं का 80 फीसदी निर्माण पूरा, दिसंबर तक परियोजना शुरू करने का लक्ष्य
5146 मेगावाट हो जाएगा प्रदेश की उत्पादन क्षमता, 25 लाख उपभोक्ता, 20 मिलियन यूनिट खपत
मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली किरलवाड़ की मसमुर नदी पर बन रहे फरकत पुल परियोजना और 624 मेगावाट क्षमता की पिनार नदी पर बन रही किरा परियोजना शामिल हैं। इन दोनों परियोजनाओं का 80 फीसदी से ज्यादा निर्माण हो



चुका है। परियोजनाओं में उत्पादन तब समय पर शुरू होने के साथ ही जनवरी से जम्मू-कश्मीर के बिजली उत्पादन क्षेत्र में खदोतरी नजर आएगी। प्रदेश में तीन प्रमुख नदियों पिनार, सेरस और रावी पर 18000 मेगावाट क्षमता की पहचान की गई है और अब तक प्रदेश में 3540 मेगावाट का ही उत्पादन हो पा रहा है। प्रदेश सरकार को सर्दियों में बिजली की खपत खरीद के माध्यम से पूरी करना पड़ रहा है। बिजली परियोजनाओं के बढ़ने से प्रदेश में यह घाटा पूरा होने का अनुमान है। प्रदेश में इस समय 25 लाख उपभोक्ता हैं। प्रदेश में 20,000

दोनों परियोजनाओं का काम 80 फीसदी पूरा हो चुका है। अगामी तीन महीने में निर्माण पूरा होने के साथ ही दोनों परियोजनाएं उत्पादन शुरू कर देंगी। इससे प्रदेश में बिजली का उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। बिजली परियोजनाओं समय पर शुरू हो, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
-मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र (विजय), जेकेपीडीओ
मिलियन बिजली की खपत हो रही है। सर्दियों में बिजली की खपत बढ़ने और उत्पादन में कमी आने की वजह से बिजली विभाग को अतिरिक्त खरीद करनी पड़ रही है। बिजली परियोजनाओं का निर्माण पूरा होने के साथ ही प्रदेश में इस घाटे के भी काम होने की संभावना रहेगी।



सत्यमेव जयते

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF **POWER**



**Office of
Manohar Lal**
Hon'ble Union Minister of Housing & Urban Affairs and Power

